

“जनपद मुरादाबाद में लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्याएँ”

Dr. Jakil Ahmad

Assistant Professor

S.B.Degree College Jalalabad,
Kannauj (U.P)

प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वह करते रहे हैं। कुटीर उद्योगों से बेरोजगारी की समस्या तो दूर होती है। अपितु कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की माँग सम्पूर्ण विश्व में होने से राजस्व एवं विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है। किन्तु भारत जैसे विकासशील राष्ट्र की विदेशी नीति के कारण यह कुटीर उद्योग समाप्ति की ओर है और हमारे देश के 95 प्रतिशत लघु उद्योग समस्याओं से ग्रस्त होते जा रहे हैं। अगर भारत सरकार ने इन सब उद्योगों पर समुचित ध्यान नहीं दिया तो वह दिन दूर नहीं जब बहुराष्ट्रीय कम्पनी अपने मायारूपी जाल से भारत की रीढ़ कुटीर उद्योग को समाप्त कर देगी और भारत में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या हो जायेगी और हमारे देश को आत्मनिर्भर होने से रोक देंगे। आवश्यकता है देश के घरेलू उद्योगों पर समुचित ध्यान देने की देश के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करने की, कुटीर उद्योग के सम्बंध में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने विचार रखा था कि – मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि हमारे हिन्दुस्तान जैसे राष्ट्र में जहाँ लाखों आदमी बेकार पड़ें हैं, लोग ईमानदारी के साथ अपनी रोटी कमा सकें इसके लिए उनके हाथ पैरों को किसी न किसी काम में लगाये रखना जरूरी है। खादी और कुटीर उद्योग उनके लिए आवश्यक हैं। भारत सरकार कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर योजनाएँ बनाते ही स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी को खेदपूर्वक कहना पड़ा कि “ भारत सरकार जब किसी धन की घोषणा करती है तो धन अभ्यर्थी तक पहुँचते –पहुँचते 10 प्रतिशत ही शेष रह जाता है। इसका मुख्य कारण है कि योजनाओं के मध्य दलालों की संख्या अधिक होती है।” चूँकि भ्रष्ट अधिकारियों की भरमार है। कार्यशैली के कारण इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। कुछ ही व्यक्तियों तक इस योजनाओं का लाभ पहुँचता है। जिससे अन्य व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ किसी भी रूप में नहीं मिल पाता है। हमारी सरकार कुटीर उद्योगों के विकास के लिए कटिबद्ध है। किन्तु आवश्यकता जन मानस तक सभी योजनाओं को सही रूप में पहुँचाने की जिससे की देश के विकास में सहयोग हो तभी लघु एवं कुटीर उद्योग का भविष्य उज्ज्वल होगा।

जनपद मुरादाबाद की स्थिति :- ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जनपद मुरादाबाद महाभारत काल में उत्तरी पंचाल राज्य का अभिन्न अंग था। जिसकी राजधानी अहिच्छत्र (वर्तमान में बरेली जनपद का रामनगर थी) को कहते हैं। प्रारम्भ में कहते हैं कि मुरादाबाद का नाम रूस्तमनगर ही था लेकिन बाद में रूस्तम खाँ ने मुगल सम्राट शाजाहाँ को खुश करने के लिए उसके बेटे मुराद के नाम पर इस का नाम मुरादाबाद रख दिया। तब से लेकर आज तक इसे मुरादाबाद के नाम से ही जाना जाता है।

जनपद मुरदाबाद रुहेलखण्ड भौगोलिक क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है जिसका अक्षांशीय विस्तार 28° 19' उत्तरी अक्षांश से 29° 16' उत्तरी अक्षांश तक एवं देशान्तरीय विस्तार 78° 23' पूर्वी देशान्तर से 78° 59' पूर्वी देशान्तर के मध्य विस्तृत है। जनपद मुरादाबाद का भौगोलिक क्षेत्रफल 3806.70 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में जनपद मुरादाबाद का उत्तर-दक्षिण अधिकतम विस्तार 115 किलोमीटर और पश्चिम-पूर्व में अधिकतम विस्तार 63 किलोमीटर है। जनपद की उत्तरी सीमा पर बिजनौर एवं उधम सिंह नगर (रुद्रपुर) जनपदों का विस्तार पाया जाता है। जबकि इसकी दक्षिणी सीमा पर जनपद बदायूँ का विस्तार है। इसके पश्चिम में नवसृजित जे.पी. नगर (अमरोहा) जनपद और पूरब में जनपद रामपुर का विस्तार पाया जाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से जनपद मुरादाबाद की स्थिति संतोषजनक है।

शहरों का विकास :- उत्तर-प्रदेश में शहरों की जैसी दुर्दशा ग्रस्त स्थिति है उसे देखते हुए जिन भी उपायों से इनका उद्धार हो सके वे किये जाने चाहिए। सार्वजनिक-निजी सहभागिता से प्रमुख शहरी के कार्याकल्प की जो योजना बनाई जाये वह उचित ही है, लेकिन देखना यह होगा कि यह योजना परवान चढ़ पाती है या नहीं, क्योंकि अभी तक का अनुभव यह बताता है कि राज्य सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर विकास कार्य कर्मों को आगे बढ़ाने की जो कोशिशें की हैं वे मुश्किल से ही आगे बढ़ सकी हैं। इस बात की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि राज्य सरकार के द्वारा संचालित जवाहर लाल नेहरू शहरी मिशन का लाभ उठाने में भी सक्षम नहीं रही। स्पष्ट है कि शहरों को विकास के लिए समस्या सिर्फ धन की ही नहीं, बल्कि उस तन्त्र के अभाव की भी है जो शहरों को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता तो आज राज्य के ज्यादातर शहरों में बुनियादी सुविधाओं की जो समस्या है वह कैसे दूर होगी। इसके साथ ही उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विकसित हो रहे शहर बेतरतीब विकास का नमूना न बनें। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के शहरों के दिन – प्रतिदिन समस्याओं से घिरते चले जाने की मुख्य वजह उनमें बेतरतीब विकास ही है। पिछले कई वर्षों से जिले में विकास का कार्य भी बहुत

हुआ है जो सड़के एक लेन हुआ करती थी बे अब चार लेन की हो गई, लेकिन विडंबना है कि देश के औद्योगिक नक्शे में अब यह औद्योगिक जिला पिछड़ता जा रहा है।

जनसंख्या: निम्न तालिका से जनपद मुरादाबाद की नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की वास्तविकता स्थिति का ज्ञान होता है।

तालिका – 1

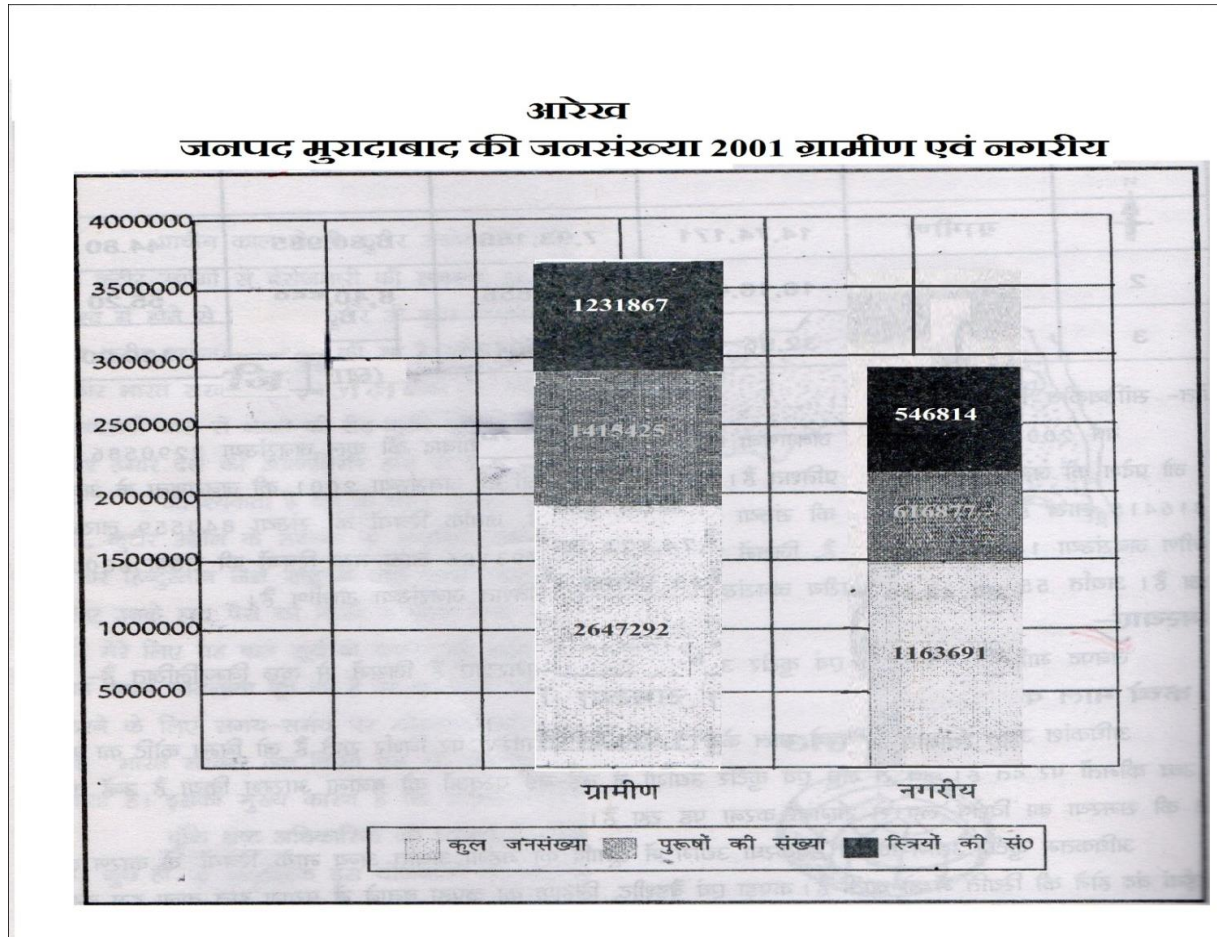
जनपद मुरादाबाद की जनसंख्या (2001) ग्रामीण एवं नगरीय

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	कुल जनसंख्या	पुरुषों की संख्या	स्त्रियों की संख्या	प्रतिशत
1.	ग्रामीण	2647292	1415425	1231867	53.46
2.	नगरीय	1163691	616877	546814	46.54
3.	योग	3810983	2032302	1778681	100.00

स्रोत:- जिला सांख्यिकीय पत्रिका जनपद मुरादाबाद (2010)

वर्ष 2001 मुरादाबाद की जनगणना के अनुसार जनपद मुरादाबाद की कुल जनसंख्या 3810983 लाख है। जनपद में नगर क्षेत्रों की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 1163691 लाख है। जिसमें पुरुषों की संख्या 616877 लाख है, जबकि स्त्रियों की संख्या 546814 लाख है। ग्रामीण जनसंख्या 2647292 लाख है। जिसमें पुरुषों की संख्या 1415425 लाख तथा स्त्रियों की संख्या 1231867 लाख है। अर्थात् 53.46 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या एवं 46.54 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है।

जनपद मुरादाबाद की जनसंख्या (2001) ग्रामीण एवं नगरीय रू.



समस्याएं:- जनपद मुरादाबाद में लघु एवं कुटीर उद्योगों की अनेक समस्याएं हैं जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

1- **कच्चे माल की समस्या:-** अधिकांश उद्योग एवं शिल्पी कच्चे माल के लिए स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं जो निम्न कोटि का माल भी उच्च कीमतों पर देते हैं। जब से लघु एवं कुटीर उद्योगों ने नई-नई वस्तुओं को बनाना आरम्भ किया है उन्हें कच्चे माल की समस्या का विशेष रूप से सामना करना पड़ रहा है।

अधिकतम कुटीर उद्योग जिनमें हथकरघा उद्योग में सूतादि का महंगा अर्थात् अन्य माल महंगाई के कारण कुछ इकाईयां बंद होने की स्थिति में हो जाती है। कपड़ा एवं बैडशीट, लिहाफ का कपड़ा बनाने में प्रयोग होने वाला दस नम्बर उद्योग का मूल्य पिछले एक माह में कई बार बढ़ चुका है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को पर्याप्त माल में उच्च कोटि का कच्चा माल उचित कीमत पर समयानुसार नहीं मिल पाता। मिल उद्योग के एजेंट उच्च कोटि का कच्चा माल पहले से ही खरीद लेते हैं। गरीब कारीगरों को जो साधन और संगठन के अभाव में उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। निम्न कोटि के कच्चे माल पर ही संतोष करना पड़ता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्थानीय व्यापारियों से ही कच्चा माल खरीदते हैं कभी-कभी आवश्यकतानुसार ठीक समय पर कच्चे माल की प्राप्ति भी कठिन हो जाती है।

2. वित्तीय कठिनाईयां— लघु एवं कुटीर उद्योगों में वित्त का ऋण की प्राप्ति से सम्बन्धित मुख्य समस्या है। हमारे छोटे उत्पादकों के लिए वित्त की कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं है। साधारणतः आधुनिक बैंकों के साथ इनका कोई विशेष लेन-देन नहीं रहता है। महाजनों और सरकारी ऋण समितियों का सहयोग भी मुख्यतः कृषि को ही प्राप्त होता है। फलस्वरूप अनेक छोटे उत्पादक काफी बड़ी सीमा तक वित्त के अभाव में कार्य करते हैं। इससे उत्पादन और बिक्री के क्षेत्रों में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अधिकांश बनकर एवं शिल्पी निर्धन हैं, जो प्रतिभूति के अभाव में व्यापारिक बैंकों से सस्ती साख प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। उन्हें साहूकारों से उंची ब्याज पर ऋण लेना पड़ता है। ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का वित्तीय आधार कमजोर है। ये एकांकी या साझेदारी संगठन के रूप में चलाये जाते हैं। सीमित लाभ के कारण वे अपने लोगों का पुर्ननिवेशन नहीं कर पाते हैं।

3. कर भार की समस्या— छोटे और मध्यम आकार की औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन कर बिक्री कर तथा स्थानीय करों का असहनीय भार उठाना पड़ता है। कर निर्धारण के अन्तर्गत सरकार हथकरघों एवं शक्ति चालित करघों में भेदभाव बरतती है।

सार्वजनिक क्षेत्र को उद्योगों पर परित्यक्त अधिकतर बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए था और वह भी भारी और मूल उद्योगों के लिए। लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए तो इसका बहुत थोड़ा सा भाग दिया जाता था। इस कारण गांधीवादी अर्थशक्तियों की एक लम्बे समय से शिकायत रही है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रति तो केवल सहानुभूति ही प्रकट की गई और उत्पादन और कीमत स्तर पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं परन्तु वास्तव में कुटीर उद्योगों के लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाये गये हैं।

4. **समय पर भुगतान न मिलने और माल एकत्रित हो जाने की समस्या**— लघु एवं कुटीर उद्योगों की इकाईयों को जो माल सरकारी इकाईयों या निजी क्षेत्र की बड़ी-बड़ी इकाईयों द्वारा खरीदा जाता है। उसके भुगतान में विलम्ब होने से लघु उत्पादकों को तैयार माल स्टॉक जमा हो जाने की समस्या का सामना करना पड़ता है।

इसका परिणाम यह होता है कि कारीगर अपने काम के प्रति उदासीन हो जाता है। उसकी फिर यही धारणा शेष रह जाती है। “जैसा पैसा, वैसा काम” वह जान बूझकर काम में जल्दबाजी करता है। और निम्न कोटि की चीजे बनाने लग जाते हैं। इससे गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। आगे चलकर बिक्री पर विशेष रूप से विदेशी मण्डियों पर इसका प्रभाव और भी बुरा पड़ता है। इससे कला कारीगरों में उत्तरोत्तर हास होता है। कारीगरों की नेतिकता भी गिर जाती है और साथ ही मण्डी का क्षेत्र वस्तुओं की साख से कम हो जाती है।

5. **विपणन सम्बन्धी कठिनाईयें**— उपभोक्ताओं की रुचियों में परिवर्तन, विज्ञापन एवं प्रचार के सीमित साधन, वृहद उद्योगों की प्रमापीकृत वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा आदि कारणों से लघु एवं कुटीर उद्योगों को अपना उत्पादित माल बेचने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है बहुधा ग्रामीण शिल्पी अपना तैयार माल साहूकार एवं ठेकेदारों के हाथों में बेचते हैं, जिससे उन्हें हानि होती है। स्थानीय व्यापारी भी उन्हें उचित कीमत नहीं चुकाते।

6. **प्रबन्धकीय कठिनाईयें**— लघु एवं कुटीर उद्योगों के संचालकों में परस्पर संगठन एवं तालमेल का अभाव है। वे उत्पादन एवं प्रबन्ध की आधुनिक रीतियों से अनभिज्ञ हैं। वे परम्परागत विधियों से उत्पादन करते हैं जो अपेक्षाकृत महंगा पड़ता है। हथरघा निर्मित वस्त्रों का मिल की तुलना में होना आदि तुलनात्मक लाभ कमी रहता है।

7. **बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा** :— लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित माल की अपेक्षा बड़े उद्योगों का निर्मित माल सस्ता और आकर्षक होता है। बड़े उद्योगों के पास माल के विज्ञापन एवं प्रचार हेतु विस्तृत साधन होते हैं। उनके साथ प्रतियोगिता में लघु एवं कुटीर उद्योगों को हानि उठानी पड़ती है।

अधिकतम उद्योगों में आयात किये गये कच्चे माल की प्राप्ति में विशेष कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि एक ओर तो उत्पादन व्यय बढ़ जाता है। और

दूसरी ओर निम्न कोटि का माल तैयार होता है, जिससे बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता में इन उद्योगों की शक्ति और गिर जाती है।

8. सांख्यिकीय संमको का अभाव :- सांख्यिकीय संमको औद्योगिक नियोजन के प्रमुख आधार होते हैं किन्तु भारत में लघु और कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित पूर्ण विश्वसनीय एवं विस्तृत संमको का अभाव पाया जाता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात संमको संकलन की जो व्यवस्था की गई है वह अपर्याप्त है। अतः कुटीर उद्योग में इसकी अत्यधिक न्यूनता है।

9. नियोजन तकनीक की समस्या :- औद्योगिक नियोजन में श्रम गहन या पूंजी गहन तकनीक अपनाई जाती है। यद्यपि औद्योगिकरण की गति तेज करने के लिए पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग आवश्यक होता है, किन्तु भारत में पूंजी की न्यूनता एवं श्रम गहन तकनीक का प्रयोग आवश्यक बना दिया है। जनपद मुरादाबाद के कुटीर उद्योगों में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण उत्तर भारत में कुटीर उद्योगों में ही पूंजी गहन का पूर्णतया अभाव है। यह पूर्ण रूपेण श्रम-गहन तकनीक पर आधारित है।

10. प्रशिक्षित एवं तकनीकी सेवा वर्ग का अभाव :- शिक्षा के निम्न स्तर और प्रशिक्षण की सुविधाओं की न्यूनताओं के कारण भारत में प्रशिक्षित एवं तकनीक सेवा कर्मियों का अभाव बना रहता है यह कुटीर उद्योगों में विवेकीकरण विविधिकरण एवं आधुनिक विशेषकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है परिणामतः इसका औद्योगिक विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

11. उत्पादकता का निम्न स्तर :- लघु एवं उत्पादन के तौर-तरीके और साज-सामान पुराने और निम्न कोटि के होते हैं। वर्तमान काल में विज्ञापन में उन्नति की है जिसके फलस्वरूप उद्योग धन्धों की व्यवस्था तथा उत्पादन विविधों और उपकरण आदि में आश्चर्यजनक उन्नति हुई है किन्तु अभी तक इस वैज्ञानिक उन्नति का देश के लघु एवं कुटीर उद्योगों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अनेक गरीब एवं अशिक्षित कारीगर आज भी पुराने उपकरणों और साज सामान के साथ दकियानूसी तरीकों पर जोर डाला जाता है इससे एक तो उत्पादन कम होता है और दूसरी जो वस्तुएं तैयार होती हैं वे पुराने ढंग और निम्न कोटि की होती हैं साथ ही उत्पादन लागत भी अधिक होती है।

12. कृषि का पिछड़ापन :- भारत की औद्योगिक संरचना में सूतीवस्त्र, चीनी, वनस्पति आदि उपभेक्ता वस्तु उद्योगों का प्रमुख स्थान है जो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है। भारतीय कृषि का पिछड़ापन इसके उत्पादन में त्वरित होने वाले उतार-चढ़ाव महत्वपूर्ण आवश्यक उद्योगों के विकास में प्रमुख बनी हुई है।

13. पूंजीगत वस्तुओं का प्रभाव :- हमारे देश की केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न प्रान्तों में अनेक बार राज्य सरकारें परिवर्तित हो जाती हैं। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि आने व जाने वाली सरकार को भी पूंजीगत वस्तुओं की नीतियों का प्रभाव कुप्रभाव देशी व कुटीर उद्योगों पर निश्चयात्मक होता है। अतः इसमें तनिक भी ढुलमुल नीति कुटीर उद्योगों के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियोजनकाल मते भारत ने उल्लेखनीय औद्योगिक प्रगति की है। किन्तु इस देश में अनेक कमियाँ रह गई थी। जैसे – औद्योगिक विकास की धीमी गति रहने के कारण पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास की वास्तविक दर निर्धारित लक्ष्य से नीची रही है। औद्योगिक विकास की दर में स्थिरता का अभाव भी रहा है। अनेक वर्षों में यह ऋणात्मक भी हो गई है।

14. आवश्यक समन्वय का अभाव :- लघु एवं कुटीर उद्योगों में विकास में आवश्यक समन्वय का अभाव सर्वद्वय ही रहा है। उदाहरण के लिए टिकाऊ उपभेक्ता पदार्थों का उत्पादन तथा उस पर आधारित उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाये रखने में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। फलतः कच्चे माल के उत्पादन के अनुसार इन उद्योगों का उत्पादन की घटता बढ़ता रहा है। यदि कूलर, फ्रिज, टेलीविजन आदि विलासपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है, तब इनके लिए आवश्यक विद्युत आपूर्ति की समस्या बनी रही है।

15. क्षमता का अल्प उपयोग :- लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास में एक अन्य समस्या जो वर्तमान में सम्मुख आयी है, वह है, क्षमता का अल्प उपयोग। अकुशल कार्य संचालन इसका प्रमुख कारण है। प्रयुक्त क्षमता के इस्तेमाल के लिए किये गये विभिन्न प्रयासों के बावजूद अनेक उद्योगों के सम्बन्ध में 45 से 60 प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त पड़ी हुई है। साथ ही इस क्षेत्र में बिमारी इकाईयों की संख्या बहुत बढ़ी है और तेजी से बढ़ भी रही है। छोटे उद्योगों का प्रबन्ध साधारणतया उनके मालिकों के हाथ में होता है जिसमें प्रायः कुशल प्रबन्धन की निपुणता नहीं होती। संकुचित ढंग का श्रम विभाजन न होनेके कारण यहाँ विशिष्टीकरणके विभिन्न लाभ उपलब्ध नहीं हो पाते।

16. विद्युत आपूर्ति की समस्या :- लघु एवं कुटीर उद्योग में विद्युत आपूर्ति की समस्या का सामना भी करना पड़ता है जिसके कारण संयंत्रों की क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं किया जाता है। साधनों की और छोटे पैमाने का उत्पादन कार्य चलाने से इनके लिए अपनी ओर से बिजली सृजन का संयन्त्र लगाना संभव नहीं है। हथकरघा उद्योग में हैण्डलूम-पावरलूम, काट उद्योग एवं धातु उद्योग में कार्यरत उद्योगपतियों को बिजली की समस्या को सहना पड़ता है। यह समस्या विकट रूप धारण किये हुए है। जो कि कई-कई घंटे गायब रहती है जिससे कार्य में रुकावट आ जाती है और आर्डर लिय हुआ माल समय पर तैयार नहीं हो पाता जिससे उपभोक्ताओं को समय पर तैयार माल न मिलने पर परेशानी उठानी पड़ती है। जनपद मुरादाबाद में लगातार बिजली कटौति के कारण पीतल उद्योग चौचट हो जायेगा। हजारों कारीगरों और उद्यमियों के सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई हैं कि अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं।

17. उचित भंडारण का अभाव :- जनपद मुरादाबाद में कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत कई ऐसी खाद्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिनको संरक्षण की आवश्यकता होती है। गुड़, एवं खाण्डसारी उद्योग, कृषि उद्योग, पीतल उद्योग, हथकरघा उद्योग, इनके सामने यही समस्या होती है कि इन सब वस्तुओं के लिए उचित भण्डारण की व्यवस्था नहीं है। उद्योग में निर्मित वस्तुओं के जमा करने व संरक्षण की सुविधा का नितान्त अभाव है।

18. सहकारिता का अभाव :- लघु एवं कुटीर उद्योगों के सामने यह समस्या भी मुख्य रूप से आती है कि इन उद्योगों में सहकारिता का अभाव है। औद्योगिक सहकारी समितियों एवं संघ के अभाव में इन उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों को निर्मित माल खरीदने, बेचने, माल के उत्पादन तथा ऋण आदि की प्राप्ति में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अंतिम सांसे ले रहा है मुरादाबाद का पीतल उद्योग:- मुरादाबाद भारत के उत्तर-प्रदेश प्रान्त का एक नगर है जो कि पीतल हस्तशिल्प के निर्माण के लिए जाना जाता है। रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका निर्यात केवल भारत में ही नहीं अपितु अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, और मध्य पूर्व एशिया आदि देशों में भी किया जाता है। मुरादाबाद विशेष रूप से प्राचीन समय की हस्तकला, पीतल के उत्पादों पर की रचनात्मकता और हार्न हैडीक्राफ्ट के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है।



पीतल नगरी मुरादाबाद के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है। ब्रासवेयर के काम में लगातार गिरावट हो रही है। अब इसका स्थान एल्युमिनियम और आयरन के उत्पाद लेते जा रहे हैं। यहाँ के उद्यमियों का कहना है पिडले दस वर्षों में उन्होंने खुद को दूसरी धातुओं की तरफ न मोड़ा होता तो बर्बाद होने के सिवा कोई चारा नहीं होता। इसकी वाजिब बजेह भी है— कच्चे माल की कमी, मांग में जबर्दस्त गिरावट, दूसरी धातुओं की अपेक्षा कृत कम कीमत और सरकारी विभागों द्वारा समय-समय पर पैदा की जाने वाली अड़चने। मुरादाबाद में बने मेटल उत्पाद अमेरिका, यूरोप ब्रिटेन, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया, और मध्यपूर्व के देशों तक निर्यात किये जाते हैं। इनमें बर्तन, लैंप, बस, हुक्का, कलश, मीनार, गिफ्ट आइटम, कैंडल लोडर, प्लेटर्स, टेग्लोब, पूजा के आइटम, बॉक्सेज आदि प्रमुख हैं। इन उत्पादों की घरेलू बाजार में भी काफी डिमांड है। 15–20 साल तक यहाँ बने उत्पादों में ज्यादातर पीतल का प्रयोग होता था। अब यह घटकर सहज 10 फीसदी ही रह गया है। ब्रासवेयर का बमुश्किल 500 करोड़ रुपये का ही नियति होता ही है इसकी जगह एल्युमिनियम, आयरन, ग्लास, सिल्वर और लकड़ी ने ले ली है। सबसे ज्यादा ब्रास आइटम की डिमांड सेवियत संघ से मिलते थे लेकिन उसके पतन के बाद इसमें भारी गिरावट आई। उद्यमी उत्पादन में आई गिरावट के लिए बिजली आपूर्ति को बड़ा कारण मानते हैं। दूसरे राज्यों में बिजली कही सस्ती है। वे सस्ते कच्चे माल की आपूर्ति के लिए सरकारी डिपो की स्थापना की जरूरत पर भी जोर देना चाहिये। अगर सरकार सहूलियते दे दे तो निर्यात बढ़कर 15000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। यहाँ के उद्यमियों का कहना है कि चीन ने कस्कुट नाम का सफेद मेटल ईजाद किया है। अगर यह मेटल उन्हें उपलब्ध कर दिया जाए तो वे भी अंतराष्ट्रीय बाजार में मजबूती से खड़े हो सकते हैं। तकनीकी विकास में भी सरकार की मदद की जरूरत है। मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की जरूरतों को

ध्यान में रखते हुए पॉलिशिंग, प्लेटिंग ग्राइडिंग, कास्टिंग, वेल्डिंग और शोल्डरिंग आदि के वोक्ेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित किये जाने चाहिये ताकि कुशल श्रमिकों की कमी को दूर किया जा सके। औद्योगिक क्षेत्र होते हुए भी मुरादाबाद में कोई व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र नहीं है।

विश्व व्यापारी मंदी के चलते इसका प्रभाव मुरादाबाद के पीतल उद्योग पर भी पड़ा है। पिछले तीन वर्ष के दौरान एक चौथाई पीतल इकाईया बंद हो चुकी है। व अन्य इकाईया बंदी होने के कगार पर है। मंदी के चलते पीतल उद्यमियों ने पीतल उत्पादन भी कम कर दिया है।

लघु उद्योगों व छोटे-छोटे उद्यमियों की कमर तोड़ दी है। जिसका सीधा प्रभाव छोटे-छोटे व्यापारियों पर पड़ा है। दिन भर में लगभग 40 प्रतिशत उत्पादन कम हो गया है। दिन में बिजली आपूर्ति होने पर भी मशीनें चलती हैं। मंदी को देखते हुए व्यापारियों ने जनरेटर चलाकर पीतल उत्पादन बंद कर दिया है। शहर में लगभग 2000 से अधिक श्रमिक भी बेरोजगारी का शिकार हुए हैं। पीतल उद्यमियों को बैंक की लिमिट चुकाना भी मुश्किल पड़ गया है।

निष्कर्ष :- सर्वेक्षण के दौरान कुटीर उद्योगों के कार्य श्रम पूंजी लाभ-हानि को बड़ी निकटता से देखा। सर्वेक्षण के दौरान अनुभव हुआ है कि कुटीर उद्योग में बहुत सारी समस्याएँ हैं। वहाँ एक तथ्य और स्पष्ट हुआ है कि कुटीर उद्योगों को अनेक रूपों में विकसित किया जा सकता है। देश की वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या जो अनेक समस्याओं की जननी है वह है बेरोजगारी। इस समस्याओं का समाधान बहुत ही सरलता से प्राप्त हो सकता है। उसका समाधान उन घरेलू परम्परागत कुटीर उद्योग पर सरकार विषेष रूप से ध्यान दें और कम पूंजी, कम श्रम में अधिक लाभ प्राप्ति की सकल्पना में एक ठोस नीति निर्धारण करें। वर्तमान युवक-युवतियों को नगरीय पलायन क्षेत्रीय विदेशी पलायन रोका जा सकता है। प्रति वर्ष नगरीय क्षेत्रों की ओर रोजगार हेतु अनेक परिवार पलायन कर जाते हैं। परन्तु वहाँ पर भी मात्र निराशा के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। घरेलू रोजगार जैसे कुटीर उद्योगों को विभिन्न प्रकार से विकसित करके अनेकों रोजगार व लाभ प्राप्त कराया जा सकता है।

सन्दर्भ-सूची

1. ए. एन. अग्रवाल – “इण्डस्ट्रियल प्रब्लम ऑफ दण्डिया” दिल्ली – (1956)
2. के. एस. बस – प्लेस एण्ड प्रब्लम ऑफ स्माल इण्डस्ट्रीज कोलकता – (1957)
3. डी. एच. भूटानी – “ऑन विलेजे इण्डस्ट्रीज प्रोग्राम खादी ग्रामोद्योग-वाल्थूम13 (1969)
4. सी. एच. दास गुप्ता – “सर एण्ड कॉटेन इण्डस्ट्रज” मुम्बई (1970)
5. मुरादाबाद गजेटियर – इलाहाबाद
6. जिला सांख्यिकीय विभाग मुरादाबाद
7. आर. एल. रावत – हैण्डलूम इण्डस्ट्रीज (1969)
8. दैनिक जागरण- 4 नवम्बर 2015 (मुरादाबाद)
9. अमर उजाला – 15 सितम्बर 2015 मुरादाबाद
10. स्वयं सर्वेक्षण द्वारा –